पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र वर्ष 15, अंक 2/2014

…✍ जरूरी है आर्थिक सुधार

जनता ने नरेन्द्र मोदी के हाथ मजबूत कर उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया है। नई सरकार की सही परीक्षा अब उसके कार्य निष्पादन के तौर-तरीकों से होगी। जो सपने चुनाव से पहले दिखाए गए थे, उनको समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का दायित्व बोझ नई सरकार पर है। उसे अपार चुनौतियों से जूझते हुए कई साहसिक निर्णय लेने होंगे।

विरासत में मिली बिगड़ी आर्थिक हालत को पटरी पर लाने और उच्च विकास दर को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता से संबंधित सुधारों को लागू करना होगा। पिछली सरकार की ढुलमुल नीतियों और भ्रष्टाचार के मामलों से हुई बदनामी के कारण देशी और विदेशी निवेशकों के आत्मबल को काफी धक्का लगा।

फलस्वरूप निवेशकों के कम रुझान से विकास और अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव दर्ज किया गया। अब सरकार को निवेशकों के लिए नया माहौल तैयार करना होगा। इसके लिए पारदर्शी व ठोस नीतियां बनानी होंगी। निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की योजनाओं व नियामक संस्थाओं के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार करना आवश्यक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से रोजगार के अवसर मिलेंगे साथ ही उत्पादकता में भी वृद्धि संभव हो सकेगी।

अच्छे दिन लाने के वादे को अमलीजामा पहनाने के लिए भ्रष्ट नौकरशाही पर नियंत्रण के साथ प्रशासनिक सुस्ती को दूर कर तेज गति से मामलों का निपटारा हो सके, इसके लिए नौकरशाही में सरकार के प्रति विश्वास पैदा करना जरूरी है।

यह भी कटु सत्य है कि जनता को सरकार से जितनी उम्मीदें हैं, वहीं सरकार के सामने अनेक चुनौतियां भी हैं। आशा है सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए समयबद्ध रणनीति तैयार करेगी।

इस अंक में...

■ आवास योजना में मनमर्जी का खेल 3
■ भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या-लोकायुक्त 5
■ नये विधायकों के हाथ लगी लॉटरी 7
■ रिन्यूअल एनर्जी की है अपार संभावना 8
■ पकड़वाएं बाल श्रम के गुनहगारों को 10

राजनीतिज्ञ और ब्यूरोक्रेट्स में बेहतर समन्वय की जरूरत: संजय बारू

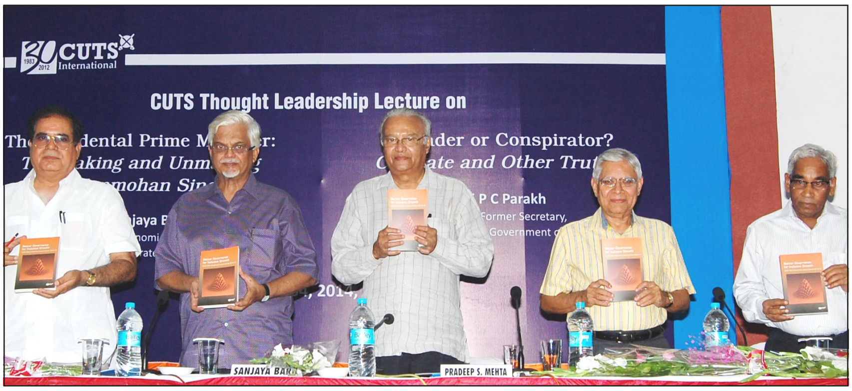

देश के विकास में सरकार तभी सफल हो सकती है जब राजनीतिज्ञों और ब्यूरोक्रेट्स के बीच बेहतर समन्वय हो। दोनों के बीच समन्वय की कमी व दबाव में काम करने से कई बार गलत निर्णय भी करने पड़ जाते हैं और उनके लिए उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ जाती है। यह विचार पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह के प्रेस सलाहकार रहे और अपनी किताब 'दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनस्टर' से चर्चा में आए जियो इकोनोमिक्स एण्ड स्ट्रेटजी, इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टॅडीज के निदेशक संजय बारू ने कट्स के अंतरराष्ट्रीय जन नीति केन्द्र (कट्स इन्टरनेशनल पब्लिक पॉलिसी सेन्टर) के कार्य शुभारम्भ के अवसर पर 5 जुलाई 2014 को जयपुर स्थित एचसीएम रीपा के भगवत सिंह मेहता सभागार (नेहरू भवन) में आयोजित 'थॉट लीडरशिप लेक्चर' में व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि अपनी किताब में उन्होंने किसी एक नेता को फोकस या टारगेट नहीं किया, बल्कि कामकाज के तौर-तरीकों को फोकस करना चाहते थे। यह जरूर है कि उन्होंने 'द मेकिंग एण्ड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह' पुस्तक के लेखन में सरकार की कई गलतियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा मुझे इस किताब के लेखन में पार्टी भी बनना पड़ा, पर मैंने वही लिखा जो मैंने अनुभव किया। इस अवसर पर 'थॉट लीडरशिप लेक्चर' में कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव तथा एक और चर्चित पुस्तक 'क्रूसेडर कॉन्सपीरेटर-कोलगेट एण्ड अदर ट्रुथ्स' के लेखक पी.सी.पारख ने कहा कि राजनैतिज्ञ यदि अपनी चलाएंगे तो ब्यूरोक्रेट्स केवल पब्लिक सर्वेन्ट बन कर रह जाएगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री नरपतसिंह राजवी ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर योजना बनाने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि कट्स के पब्लिक पॉलिसी सेंटर से जनता और सरकार के बीच संवाद कायम करने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम के प्रारंभ में कट्स के महामंत्री प्रदीप महता ने संस्था का परिचय देते हुए सम्पादित विभिन्न गतिविधियों का सारांश प्रस्तुत किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि पॉलिसी सेन्टर सिर्फ पॉलिसी बनाने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके क्रियान्वयन में भी सहयोग करेगा।

पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी एवं कट्स इन्टरनेशनल पब्लिक पॉलिसी सेन्टर के अध्यक्ष अशोक झा ने प्रारम्भिक उद्‌बोधन तथा प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव व कट्स के अध्यक्ष एम.एल. मेहता ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारियों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, गणमान्य नागरिकों और व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा सिविल सोसायटियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

जिला स्तरीय किसान आमुखीकरण कार्यक्रम

समय की मांग: किसान फिर से अपनाएं जैविक खेती

आज के दौर में आधुनिक कृषि से मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से जहां खाद्य पदार्थ जहरीले हो रहे हैं, वहीं प्राकृतिक वातावरण भी असंतुलित हो रहा है। मद्देनजर, हमें फिर से सतत कृषि को बढ़ावा देना होगा, जिससे हम प्राकृतिक स्त्रोतों का भरपूर उपयोग करते हुए स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ा सकें। हमें जैविक खेती के प्रचार-प्रसार और इसके प्रति जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि, यह हमारे किसान भाईयों के लिए भी ज्यादा फायदेमंद होगा।

उक्त तथ्य कट्स द्वारा जयपुर में आयोजित जिला स्तरीय किसान आमुखीकरण कार्यक्रम में उभर कर सामने आए। कार्यक्रम में आमंत्रित सभी विषय विशेषज्ञों ने यह आम राय व्यक्त की और बताया कि जैविक खेती से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा।

तकनीकी सत्रों में जैविक खेती की आवश्यकता व महत्व पर डॉ. ए.के.गुप्ता, प्रोफेसर एग्रोनोमी विभाग, दुर्गापुरा कृषि फार्म; जैविक खेती की व्यावसायिक संभावनाओं पर मोरारका फाउण्डेशन के समन्वयक आनन्द शुक्ला; उर्वरक व मृदा प्रबंधन पर सोम सोसायटी के सचिव हरीमोहन गुप्ता व कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. एस.एस.राठौड़; कीट प्रबंधन पर जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के डॉ. श्रीराम शर्मा तथा जैविक खेती के प्रमाणीकरण व इससे संबंधित किसानों की आम समस्याओं पर दुर्गापुरा कृषि फार्म के उद्यानिक विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. एस. मुखर्जी ने संभागियों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। सभी विशेषज्ञों के संबोधनों में जो प्रमुख बात निकलकर आई वो जैविक खेती को एक सुव्यवस्थित रूप देने से संबंधित है जिससे कि सतत कृषि को बढ़ावा मिल सके।

कार्यक्रम के प्रारंभ में वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक दीपक सक्सेना के स्वागत उद्‌बोधन के पश्चात परियोजना समन्वयक अमरजीत सिंह ने प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि यह परियोजना राजस्थान के चयनित छह जिलों जयपुर, दौसा, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व उदयपुर के कुल 102 ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जैविक पदार्थों के उपभोग को बढ़ावा देना है। इसके लिए पिछले दो वर्षों के दौरान शोध, प्रशिक्षण, पैरवी, जन जागरण अभियान व संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

कार्यक्रम के दूसरे दिन सभी संभागियों को दुर्गापुरा कृषि फार्म व गौसेवा संघ, दुर्गापुरा गौशाला का भ्रमण करवाकर उनको प्रायोगिक व व्यवहारिक जानकारी दिलाई गई, जिसमें जैविक खेती से जुड़ी विभिन्न कृषि प्रणालियों, उपचार तथा गोबर व गोमूत्र का विभिन्न तरीकों से सदुपयोग सम्मिलित है। कार्यक्रम में जयपुर जिले की सभी 13 पंचायत समितियों के करीब 51 किसानों, जिनमें महिला कृषक भी शामिल थीं, के साथ-साथ जयपुर शहर के जैविक खेती पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रतिस्पर्धा व पारदर्शिता से सुधारों को लागू करें

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली को कट्स संस्था की ओर से मुद्रास्फीति और उच्च विकास दर को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता से संबंधित सुधारों को तुरंत प्रभाव से लागू करने का सुझाव दिया गया है।

वित्त मंत्री की दिल्ली में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में भाग लेने के बाद कट्स इंटरनेशनल के महामंत्री प्रदीप महता ने इस बात पर बल दिया कि सरकार के पूर्ण एवं स्थाई बहुमत प्राप्त कर लिया है इसलिए उसे पूर्ण रूप से भारत को वर्ष 2030 तक दस ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कार्य करना चाहिए।

ज्ञापन के माध्यम से महता ने कहा है कि वर्णित क्षेत्रों में सुधारों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने एवं सर्वोत्तम विकास दर प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो कि कमजोर व पिछड़े उपभोक्ताओं की जरूरतों की रक्षा करने, सुशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

चर्चा के दौरान महता ने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति, सार्वजनिक क्रय अधिनियम व राष्ट्रीय सार्वजनिक क्रय नीति, राष्ट्रीय हरित ऊर्जा कोष बनाने, वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करने जैसे कई सुझाव देते हुए उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता जताई। वित्तमंत्री जेटली ने वार्ता के दौरान सामाजिक संस्थाओं और उपभोक्ता संगठनों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए बजट में वित्तीय प्रावधान करने का आश्वासन दिया।

कल्याण कोष का हो सही इस्तेमाल

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो प्रदेश की वित्त मंत्री भी है ने वर्ष 2014-15 के बजट हेतु पूर्व परामर्श करने के मकसद से प्रदेश के गैर सरकारी, सामाजिक और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की।

बैठक में कट्स के महामंत्री प्रदीप महता ने उपभोक्ता कल्याण कोष को सुदृढ़ बनाए जाने का सुझाव देते हुए कहा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा व्यापारियों के दावों के निस्तारण में यदि रिफण्ड आदेश होता है, तो उक्त राशि चूंकि उपभोक्ता की होती है, अतः पुनः भुगतान व्यापारी को नहीं किया जाकर उक्त राशि उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा की जानी चाहिए। उन्होंने उपभोक्ता क्लबों के माध्यम से उपभोक्ता आन्दोलन को गति दिए जाने का परामर्श देते हुए मुख्यमंत्री को कट्स की ओर से एक ज्ञापन दिया।

बैठक में उपस्थित अन्य संस्था प्रतिनिधियों ने भी प्रदेश में उपभोक्ता नीति लागू करने, उपभोक्ता कल्याण कोष का सही इस्तेमाल करने, महंगाई पर नियंत्रण, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने, स्कूली शिक्षा में सुधार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के बारे में कई सुझाव रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखेगी और प्रदेश के विकास में स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सहयोगी बनाएगी।

सही योजना उचित कदम! सुशासन का यह है धर्म!!

पेयजल परिवहन में करोड़ों का घोटाला

जलदाय विभाग में पेयजल परिवहन के नाम पर करीब पांच करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। जयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में हुए इस घोटाले का खुलासा महालेखाकार की जांच में हुआ है। महालेखाकार ने जलदाय विभाग के आला अफसरों को अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिखा है।

बताया जाता है कि महालेखा कार्यालय की ओर से जलदाय विभाग के जयपुर जिला खण्ड द्वितीय के यहां वित्तीय वर्ष 2012-13 के लेखा-जोखों की जांच की गई। करीब दो महीने की गई इस जांच में जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा, कोटपूतली और विराटनगर क्षेत्र के गांवों में टेंकरों से पेयजल परिवहन में गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। इन तीनों क्षेत्रों में ही करीब पांच करोड़ रुपए का घपला सामने आया है, लेकिन जलदाय विभाग के आला अफसर चुप्पी साधे बैठे हैं। *(दै.न., 21.06.14)*

तीन साल में बढ़ा एक ही कदम

प्रदेश के शहरी लोगों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के संबंध में सिफारिशें देने के लिए शहरीकरण आयोग भले ही तीन साल पहले बन गया हो, लेकिन अब तक पहले कदम के रूप में वह सिर्फ अंतरिम रिपोर्ट ही दे पाया है। इस रिपोर्ट में भी प्रमुख चुनौती और समस्याओं की अनदेखी की गई है। राज्य सरकार ने कमियां गिनाते हुए इन्हें दुरूस्त करने की हिदायत दी है।

रिपोर्ट में जो भी चुनौती और समस्याएं बताई गई है उनमें से अधिकतर के समाधान के लिए स्पष्ट सिफारिश भी नहीं दी गई है। यह ही नहीं, शहरों के विकास के लिए जिम्मेदार शहरी निकाय, जलदाय विभाग, विद्युत निगम व दूरसंचार विभाग आदि के बीच तालमेल की आवश्यकता का रिपोर्ट में स्पष्ट जिक्र तक नहीं किया गया है। जबकि इन विभागों में सामंजस्य की कमी का खामियाजा शहरी जनता को भुगतना पड़ता है। *(रा.प., 03.04.14)*

खा गए बच्चों का 'निवाला'

कोटा में सरकारी स्कूलों में पोषाहार पकाने और वितरण करने का काम नंदी फाउण्डेशन को सौंप रखा था। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से नंदी फाउण्डेशन तक गेहूं और चावल की आपूर्ति का काम नई धानमंडी स्थित कोटा को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी को दिया गया था। नंदी फाउण्डेशन ने 24 फरवरी 2014 को पोषाहार तैयार करने से हाथ खींच लिए थे और स्टॉक में मौजूद 500 बोरी गेहूं और 200 बोरी चावल वापस भारतीय खाद्य निगम में जमा कराने के लिए को-ऑपरेटिव सोसायटी के परिवहन ठेकेदार रवि कुमार को सुपुर्द कर दिए। लेकिन ठेकेदार ने गेहूं और चावल को गायब कर दिया।

जिला परिषद प्रशासन की ओर से पोषाहार के लिए वितरित गेहूं और चावल का सत्यापन करने पर मामला उजागर हुआ। इससे अब अधिकारियों में हड़कम्प मचा हुआ है। पोषाहार का वितरण जिला परिषद प्रशासन की निगरानी में होता है। *(रा.प., 18.06.14)*

नहीं मिल रही फसल की सही कीमत

प्रदेश में फसल की उत्पादन लागत और केन्द्र सरकार की ओर से तय किया गए समर्थन मूल्य में काफी अन्तर है। खासतौर पर यह सरसों, गेहूं और चना जैसी कई फसलों में है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य तक नहीं मिल रहा इससे खेती घाटे का सौदा बन गई है। कई फसलों में यह अन्तर इतना है कि राज्य सरकार की ओर से घोषित बोनस से भी पार नहीं पड़ रही।

राज्य के कृषि मंत्री का मानना है कि कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय दरें तय करता है, पर यह कम है। भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने उत्पादन लागत दरें तय की थी। प्रदेश में इस बार रिपोर्ट आने पर केन्द्र सरकार से बात की जाएगी और प्रयास करेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़े। *(रा.प., 30.04.14)*

सरकार को लगी 190 करोड़ की चपत

भले ही सरकार की मंशा फसल बीमा के प्रीमियम में सब्सिडी देकर किसानों को राहत देने की हो लेकिन मौज बीमा कंपनियों की हो रही है। कंपनियां प्रीमियम पर मिली सब्सिडी की राशि से भी कम मुआवजा किसानों को बांट रही है। इससे हर साल सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए की चपत लग रही है। लेकिन कंपनियों से सांठ-गांठ के चलते सरकारी मातहत अनजान बने हुए हैं।

आंकड़ों के मुताबिक कंपनियों को 2010 से 2013 के रबी और खरीफ सीजन में मौसम आधारित बीमा योजना में केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से बतौर प्रीमियम सब्सिडी 2042.86 करोड़ और फसल कटाई प्रयोग वाली बीमा योजना में रबी 2011-12 व खरीफ 2012 में 75.62 करोड़ रुपए मिले जब कि इन योजनाओं में किसानों को 1928.18 करोड़ रुपए का ही मुआवजा बांटा गया। सीधे तौर पर इससे सरकारी खजाने को 190.3 करोड़ की चपत लगी। *(रा.प., 26.05.14)*

पंचायतें नहीं हो सकी मजबूत

राज्य की पिछली सरकार के समय शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, खाद्य व नागरिक आपूर्ति तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता जैसे पांच विभाग पंचायतों को सौंप कर उन्हें मजबूत करने का दावा लगभग खोखला साबित हुआ है। सरकार ने इसके आदेश तो जारी कर दिए लेकिन हकीकत में इन विभागों की शक्तियां और बजट पंचायतों को नहीं मिल पाया।

चौथे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में पंचायतों को सौंपे गए इन विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई है। इसमें 75 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं ने कहा है कि इन विभागों का बजट उन्हें नहीं मिला और 67 फीसदी का कहना है कि इन विभागों के सारे काम उनके जरिए नहीं हो रहे हैं। *(रा.प., 12.05.14)*

आवास योजना में मनमर्जी का खेल

मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना में करोड़ों रुपए अपात्रों को बांट देने का गंभीर मामला सामने आया है। नागौर जिले के मकराना नगर परिषद में प्रदेश में सर्वाधिक करीब 3500 आवेदकों को योजना के तहत लाभान्वित करना सामने आया था।

इस पर स्वायत शासन निदेशक के निर्देश पर की गई जांच में खुलासा हुआ कि इनमें से 2500 परिवारों को 25 हजार रुपए प्रति परिवार के हिसाब से करीब 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि की बंदरबांट हुई है। जबकि करीब 1000 आवेदक ही योजना के तहत सहायता पाने के वास्तविक हकदार थे। मामले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नागौर, डीड़वाना, मेड़ता, सरवाड़ व पुष्कर पालिकाओं में भी जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। *(रा.प., 04.04.14)*

उजाले की खरीद में अंधेरगर्दी

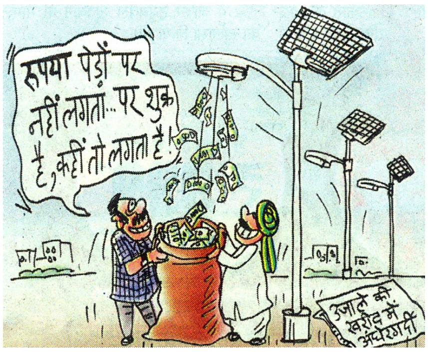

पंचायती राज विभाग की ओर से गांवों में रोशनी करवाने के नाम पर लगवाई कई सोलर लाइटों की खरीद में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। पंचायत समितियों में बीडीओ और ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच-ग्रामसेवकों के गठजोड़ द्वारा उजाले के नाम पर बरती गई अंधेरगर्दी से करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। अब सरकार में आला स्तर पर हड़कंप मचा है।

लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट की जांच में सामने आया है कि जो लाइट 21 हजार रुपए में खरीदी जानी थी, उसकी कीमत 28 हजार, 33 हजार और 49 हजार रुपए तक चुका दी गई। इतना ही नहीं सरकारी खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाने की बाध्यता होने के बावजूद कई पंचायतों में सिर्फ बातचीत के आधार पर और मौखिक आदेश से ऊंची दरों पर लाइटों की खरीद कर ली गई।

मामला चाकसू पंचायत समिति के वर्ष 2011 से 2013 की ऑडिट में पहली बार पकड़ में आया। इसके बाद मामला खुलता चला गया और कई जिलों की पंचायतों में गड़बड़ी का खुलासा हुआ।

(दै.भा., 24.05.14)

पर्यावरण सुधार की राशि तिजोरी में !

राज्य में पर्यावरण सुधार के लिए बेचा पत्थर, बजरी व अन्य मिनरल्स पर जनता से वसूले जा रहे रुपए खान विभाग अपनी तिजोरी में बन्द करता जा रहा है। पिछले डेढ़ साल से चल रहे इस वसूली अभियान में अब तक करीब 250 करोड़ रुपए एकत्रित हो चुके हैं, लेकिन पर्यावरण के नाम पर अभी तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। जबकि यह राशि पौधारोपण पर प्रति पौधा पन्द्रह रुपए खर्च की जाए तो प्रदेश में करीब 16.66 करोड़ पौधे लगाए जा सकते हैं।

पर्यावरण से जुड़े लोगों का कहना है कि खान विभाग द्वारा पर्यावरण के नाम पर राशि वसूलने के बावजूद उसे पर्यावरण पर खर्च नहीं करना जनता के साथ धोखा है।

क्लस्टरों के माध्यम से खनन क्षेत्र के आसपास सरकारी भूमि पर पौधारोपण, गांव के विकास के काम, पौधारोपण के बाद उनके बचाव के लिए चारदीवारी बनाने, विधवा व अन्य असहाय लोगों की मदद करने और पर्यावरण सुधार के कई कार्यों को इस योजना में शामिल किया गया था। *(रा--.प., 29.06.14)*

प्रशिक्षण मिला न रोजगार

राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और अकुशल व्यक्तियों को कुशल मानव शक्ति में बदलने के मकसद से शुरू हुई ट्रेन-टू-गेन योजना ने ठण्डे बस्ते में ही दम तोड़ दिया। उद्योग विभाग की उदासीनता के चलते योजना का प्रचार-प्रसार ही नहीं हो पाया। ऐसे में बेरोजगारों ने प्रशिक्षण के लिए आवेदन नहीं किया।

पिछली सरकार के कार्यकाल 2011 में शुरू की गई इस योजना में 18 से 45 साल की आयु के कम से कम दसवीं पास व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर कुशल मानव शक्ति में बदलने और उसके बाद रोजगार देने का प्रावधान था।

नियोजकों की ओर से होने वाले इस प्रशिक्षण में उन्हें वेतन या मानदेय दिया जाना था। इसका 50 फीसदी या अधिकतम 2000 रुपए की सहायता उद्योग विभाग की ओर से दी जानी थी। जालौर जिले में 2012-13 में एक भी व्यक्ति ने आवेदन नहीं किया। इससे प्रशिक्षण के लिए मिली राशि भी लेप्स हो गई। *(रा.प., 07.04.14)*

मनरेगा: 146 गांवों में रोजगार नहीं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत रोजगार देने को लेकर सरकार भले ही बड़े-बड़े दावे करे, लेकिन हकीकत में राज्य के सभी गांवों में अभी तक रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरपंच व अधिकारियों की उदासीनता के चलते पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य के 18 जिलों के 146 गांवों के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका। वहीं मार्च में रोजगार पाने वालों की सूची तैयार करने के लिए लगाए गए तीन दिवसीय शिविर में करीब सात लाख लोगों ने नाम दर्ज कराए हैं। *(रा.प., 07.05.14)*

गेहूं खरीद में करोड़ों का गठजोड़

प्रदेश में अब गेहूं की सरकारी खरीद में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों की तरह चैन सिस्टम शुरू हो गया है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद कुछ जिलों में गेहूं की खरीद के लिए राजस्थान स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन (अरएसडब्लूसी) को ठेका दिया, जिसके पास भी संसाधनों की कमी नहीं है।

इसके बावजूद उसने यही काम एक निजी कंपनी को सौंप दिया। इस सरकारी निजी गठजोड़ से सरकारी खजाने को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा वहन करने होंगे। सवाल उठता है कि क्या यह पैसा कुछ आला अफसरों और निजी कंपनियों की जेबों में जाएगा? अगर यही काम एफसीआई करती तो खजाने को 100 करोड़ रुपए की बचत होती। *(दै.भा., 29.04.14)*

कबाड़ हो रही जनता की सीएफएल

पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिजली उपभोक्ताओं के लिए मंगवाई गई सीएफएल राज्य सरकार और बिजली कंपनियों के बीच अटक कर रह गई है। कंपनियों के पास अभी स्टॉक में 5.34 लाख सीएफएल हैं, जिस पर गहलोत सरकार के नेताओं के फोटो चस्पा हैं। इसके चक्कर में न तो शेष रहे शहरी उपभोक्ताओं को सीएफएल वितरित की जा रही है और न ही खराब सीएफएल को बदला जा रहा है।

इस लेटलतीफी के चलते करीब 45 हजार सीएफएल स्टॉक में टूट-फूट चुकी हैं। फिर भी उच्चाधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। जिन उपभोक्ताओं की सीएफएल शुरू में ही खराब हो गई, उन्होंने इसे बदलने के लिए जमा कराया, लेकिन स्टॉक में माल नहीं होने का हवाला देकर उन्हें भी बदलने में टालमटोल हो रही है। लोकायुक्त एस.एस. कोठारी ने भी इस बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है।

(रा.प., 03.06.14 एवं दै.न., 24.06.14)

चोरों के हवाले करोड़ों के ट्रांसफार्मर

कंगाली से जूझ रही बिजली कंपनियों को ट्रांसफार्मर चोर जम कर चपत लगा रहे हैं। प्रदेश में पिछले पांच सालों में थ्री फेस के 24809 और सिंगल फेस के 7623 ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। जिनकी कीमत करीब 156 करोड़ रुपए हैं।

इसे कंपनियों की विजिलेंस की खामी कहें या फिर अभियंताओं की मिलीभगत, जिससे चोरों ने कुल 32432 ट्रांसफार्मरों को निशाना बनाया। इस दौरान चोरी के सर्वाधिक मामले जयपुर डिस्कॉम में ही सामने आए हैं। इसके बावजूद न तो विजिलेंस विंग को मजबूत करने पर कोई ध्यान दिया जा रहा है और न ही फील्ड अधिकारियों पर सख्ती बरती जा रही है।

(रा.प., 05.06.14)

भ्रष्ट अफसरों पर कानून का प्रहार

सीबीआई सरकार से मंजूरी लिए बिना अब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे वरिष्ठ नौकरशाहों से पूछताछ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपराधिक मामलों में अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए भी मंजूरी की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच के लिए सरकार की अनुमति लेने संबंधी कानूनी प्रावधान को अमान्य और असंवैधानिक करार दिया।

प्रधान न्यायाधीश आर.एम.लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कानून की धारा 6-ए के प्रावधान पर यह व्यवस्था दी। संविधान पीठ ने कहा भ्रष्ट नौकरशाह चाहे ऊंचे पद पर हो या निचले, सब एक समान है और उनसे एक समान ही व्यवहार करना होगा। भ्रष्टाचार पर अधिकारियों के बीच वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार राष्ट्र का शत्रु है।

(रा.प.एवं दै.भा., 07.05.14)

पैर काटने के लिए डॉक्टर ने ली घूस

मरीज का पैर काटने के बदले 2500 रुपए की घूस लेते पकड़े गए राज्य के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के सर्जिकल यूनिट हैड राजवीर आर्य की जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि यह कृत्य मानवीय संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने डॉक्टर आर्य को चांदपोल निवासी देवी शंकर छीपा की शिकायत पर 2500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। देवी शंकर ने एसीबी को शिकायत की थी कि उसके पिता के पैर में गैंगरीन था। डॉ. आर्य ने पहले उनकी एक अंगुली काटी, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ तो पैर काटने की बात कही और इसके लिए घूस मांगी।

डॉ. राजवीर आर्य ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी पेश करते हुए कहा था कि रिश्वत राशि 2500 रुपए ही है और यह अधिक नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए। *(दै.भा., 19.04.14)*

कालाधन : लाएं माफी स्कीम

उच्चतम न्यायालय के आदेश पर विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किए जाने के बीच उद्योग संगठन एसोचैम ने विदेशों में पड़े करीब 1.20 लाख करोड़ के काले धन को स्वदेश लाने के लिए सरकार को छह महीने तक माफी स्कीम लागू करने और इस दौरान घोषित की जाने वाली राशि पर 40 फीसदी कर लगाने का सुझाव दिया।

एसोचैम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल कनोरिया ने इस बारे में संगठन द्वारा तैयार रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि इस तरह की स्कीम अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे दुनिया के 20 देशों में शुरू की गई थी और उसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे थे। *(दै.न., 21.06.14)*

रिश्वत देने वाला भी हो जवाबदेह

स्वच्छ कॉरपोरेट शासन और राजनीति में ईमानदारी की जोरदार पैरवी करते हुए ब्रिटेन में रहने वाले प्रवासी भारतीय उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल ने कहा है कि भ्रष्टाचार के कैंसर को भारत से तब तक नहीं खत्म किया जा सकता जब तक कि रिश्वत देने वाले को भी रिश्वत लेने वाले के समान जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार अकेले काम नहीं कर सकता। जिस समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त होता है और जहां कोई व्यक्ति अपना कोई काम कराना चाहता है तो वहां सभी रिश्वत की पेशकश करने की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक यह नहीं समझा जाता कि रिश्वत देने वाला भी रिश्वत लेने वाले के बराबर दोषी है। *(न.नु., 28.04.14)*

जो भी रिश्वत लेगा सीधा जाएगा जेल

वित्त मंत्रालय के तीन सेवा निवृत्त सहित पांच कर्मियों व एक अन्य व्यक्ति को सीबीआई कोर्ट ने 4.20 लाख रुपए के अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) गबन मामले में चार-चार साल की जेल की सजा सुनाई। विशेष सीबीआई जज संजीव जैन ने यह सजा सुनाते हुए कहा कि सभी को कठोर संदेश दिया जाए कि कोई भी भ्रष्टाचार को छिपा नहीं सकता और किसी भी तरीके से भ्रष्ट व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता।

उन्होंने कहा कि समय के साथ समाज के छोटे वर्ग में यह धारणा बन रही है कि भ्रष्टाचार मानो सफलता का सबसे आसान रास्ता है, जो न तो सही है और न ही उचित। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करना ईमानदारी के प्रति असहिष्णुता होगी। अब यह संदेश जाए कि सफलता के लिए भ्रष्टाचार सुरक्षित और आसान नहीं बल्कि जेल जाने का मार्ग है। अब प्रत्येक दीवार पर यह लिखा होना चाहिए कि 'जो भी रिश्वत लेगा सीधा जेल जाएगा।' *(रा.प., 23.06.14)*

भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या-लोकायुक्त

न्यायमूर्ति एस.एस.कोठारी ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में बिना 'सुविधा शुल्क' के काम नहीं होने से साधारण आदमी काफी परेशान है। सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोकसेवकों पर नियंत्रण नहीं होने से भ्रष्टाचार चरम पर आ पहुंचा है। भ्रष्टाचार व घोटालों की वजह से युवाओं में क्रांतिकारी सोच उत्पन्न हो रही है।

उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दौरान यह बात कही। भ्रष्टाचार की विभीषिका से निपटने की जरूरत का विश्लेषण करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में चार पुरुषार्थ में से धर्म व मोक्ष को दरकिनार कर काम और अर्थ पर ही बल दिया जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार ने न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देशभर में जीवन दर्शन का रूप धर लिया है। आज दुनिया के 70 फीसदी देशों में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या बन कर खड़ा हुआ है। वार्ता में लोकायुक्त सचिवालय के सचिव हरिराम जाट, उप सचिव उमाशंकर शर्मा, उपखंड अधिकारी भगवती प्रसाद आदि मौजूद थे। *(दै.भा., 08.05.14)*

भ्रष्टाचार पर मुखिया की निगाहें

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के मुखिया की नजर प्रदेश के सभी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पर रहेगी। वह मुख्यालय में बैठे-बैठे माउस की एक क्लिक पर पीई, परिवाद और मुकदमों की स्थिति जान सकेंगे। इसके लिए एसीबी की प्रदेशभर की 43 चौकियों को ऑनलाइन किया जा रहा है। एसीबी अधिकारियों के मुताबिक रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से पुराने मामलों की गति पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी और लम्बित मामलों में कमी आएगी।

जिला चौकियों की कार्ययोजना पर आला अधिकारियों की सीधी नजर रहेगी, जिससे चौकी प्रभारी अब किसी मामले में चल रही जांच को लेकर बहाना या टालमटोल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि, इसके बाद इन चौकियों की पल-पल की जानकारी मुख्यालय में मिलती रहेगी और इस पर आईजी, डीआईजी और एसपी नजर रखेंगे। पीई, परिवाद, मुकदमों की जांच पर नजर से आला अधिकारी सीधे सुझाव और निर्देश भी दे सकेंगे। *(रा.प., 29.05.14)*

फिर लोकायुक्त ही देंगे भ्रष्टों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति

राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम-1973 में प्रस्तावित संशोधनों पर यदि सरकार ने मुहर लगा दी तो आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए छापा मारने से लेकर इन्वेस्टिगेशन करने व केस चलाने की अनुमति का पावर लोकायुक्त को होगा। वह भ्रष्ट अफसरों की संपत्ति भी कुर्क कर सकेंगे। मुख्यमंत्री को भी इसके दायरे में लाने की तैयारी प्रस्तावित संशोधन में है।

राजस्थान के लोकायुक्त एस.एस. कोठारी की ओर से मुख्यमंत्री को भेजे गए संशोधन प्रस्तावों पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने कर्नाटक, मध्यप्रदेश जैसे प्रभावी लोकायुक्तों वाले प्रदेशों से ब्योरा मांगा है। अन्य राज्यों में दिए गए अधिकारों पर मंथन के बाद कमेटी आगे होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त कानून में संशोधन के लिए अपनी रिपोर्ट देगी। *(रा.प. एवं दै.भा., 21.06.14)*

लोकायुक्त को ये भी अधिकार

- *राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या जांच एजेंसी की सेवाएं लेने के लिए होंगे अधिकृत। लोकायुक्त की ओर से जांच किए जाने वाले मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में होगी।*
- *जिस लोकसेवक की जांच होगी उसके ट्रांसफर व निलम्बन का अधिकार होगा। लोकायुक्त भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों को कुर्क कर सकेंगे।*
- *प्राथमिक जांच में दस्तावेजों को खुर्दबुर्द करने से रोकने के निर्देश देने की शक्ति भी होगी और अवहेलना पर 10 हजार तक जुर्माना।*
- *अभी पांच वर्ष की अवधि के मामलों की जांच कर सकते हैं अब यह अवधि सात साल होगी। वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को जाएगी। जिन मामलों में सलाह नहीं मानी गई हो, ऐसे मामले सरकार की एक्शन रिपोर्ट के साथ विधानसभा में पेश की जा सकेगी।*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
जयपुर	वीरेन्द्र सिंह यादव	कॉस्टेबल, जवाहर सर्किल थाना, जयपुर	13,000	दै.भा., 10.04.14
जयपुर	डॉ.राजवीर आर्य	सर्जरी यूनिट के प्रोफेसर, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल	2,500	रा.प. एवं दै.भा., 17.04.14
झुंझुनूं	अश्वनीकुमार शर्मा धर्मपाल यादव	थानाधिकारी, कोतवाली पुलिस थाना एएसआई, कोतवाली पुलिस थाना	2,50,000	रा.प., 30.04.14
जयपुर	पप्पू लाल सैनी	लाइनमैन, जेवीवीएनएल कार्यालय, चाकसू, जयपुर	2,000	दै.भा., 03.05.14
अजमेर	धर्म सिंह मीणा	इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मेन्टेनर,उत्तर पश्चिम रेलवे जोन	20,000	रा.प. एवं. दै.भा., 04.05.14
बीकानेर	वीरेन्द्र सिंह	रिकॉर्ड कीपर, उपनिवेशन विभाग, कोलायत	1,500	रा.प., 06.05.14
जयपुर	नरेश जाट	क्लर्क, जयपुर आवास विकास संस्थान	1,500	रा.प., 23.05.14
जोधपुर	राणाराम विश्नोई	एएसआई, महामंदिर थाना, जोधपुर	10,000	रा.प., 23.05.14
बांसवाड़ा	भगवती लाल प्रवीणकुमार मीणा अमृतलाल वशिष्ठ	एईएन, एवीवीएनएल, सिविल निर्माण शाखा जेईएन, एवीवीएनएल, सिविल निर्माण शाखा एक्सईएन, एवीवीएनएल, उदयपुर डिविजन	30,000	रा.प. एवं दै.भा., 24.05.14
हनुमानगढ़	भानीराम मेघवाल	राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग	15,000	रा.प., 27.05.14
कोटा	सत्यवीर सिंह	एसपी, कोटा (शहर)	1,50,000	रा.प., 28.05.14
डूंगरपुर	रवि कुमार गुप्ता	बैंक मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक, चुण्डावाड़ा	5,000	दै.न., 13.06.14
चित्तौड़गढ	कपिल सैन	सहायक अभियंता, पीडब्लूडी बड़ी सादड़ी उपखंड	1,00,000	दै.भा. एवं रा-.प., 15.06.14
बांसवाड़ा	ओम प्रकाश मीणा	एसडीओ, उप मंडल अधिकारी, बीएसएनएल, बागीदौरा	1,000	दै.भा. एवं दै.न., 19.06.14
धौलपुर	राजेश जाटव	हैडकांस्टेबल, नादनपुर थाना, बसेडी. धौलपुर	10,000	रा.प. एवं दै.न., 20.06.14
कोटा	कुलदीप सिंघल	मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम, कोटा	10,000	दै.भा एवं दै.न., 21.06.14
चित्तौड़गढ़	चतुर्भज रेगर नक्षत्रमल खटीक	हैड कांस्टेबल, भादसोड़ा पुलिस थाना, चित्तौड़गढ़ कांस्टेबल, भादसोड़ा पुलिस थाना, चित्तौड़गढ़	2,000	दै.भा. एवं दै.न., 21.06.14
जैसलमेर	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	एक्सईएन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना खंड 24	20,000	दै.न. एवं दै.भा., 22.06.14
जयपुर	रति राम	कांस्टेबल, जेडीए थाना, जयपुर	50,000	रा.प. एवं दै.न., 27.06.14

भाजपा को मिली प्रदेश की सभी 25 सीटें

'कट्स' द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व प्रदेश के विभिन्न जिलों में खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ता के सहयोग से कराए गए सर्वे में प्रदेश के 76 फीसदी लोगों ने बीजेपी को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना जताई थी।

प्रदेश के 67 फीसदी लोग नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना पसन्द करते थे। उनकी सभी उम्मीदें फलीभूत हुई हैं। प्रदेश में जहां सभी सीटों पर भाजपा को विजयश्री मिली, वहीं पूरे देश में एनडीए ने लोकसभा की 543 सीटों में से 336 पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अकेले दम पर ही भाजपा को 282 सीटें मिली हैं।

प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय मोदी जी और कार्यकर्ताओं को दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केन्द्र की मोदी सरकार में राजस्थान को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने बताया कि मोदी जी राजस्थान की परिस्थितियों से भलि-भांति वाकिफ है और वे यहां की तकलीफों को समझते हैं। कड़ी से कड़ी जुड़ने से प्रदेश को विकास के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार पूरे जोश से विकास योजनाएं लागू कर, आमजन की उम्मीदों को पूरा करने के प्रयास करेंगी।

संसद होगी अपराधियों से मुक्त

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 तक संसद को अपराधियों से मुक्त करने का वादा किया है। उन्होंने संसद सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दो दिन चली बहस के दौरान राज्य सभा में कहा कि दोनों सदनों को अपराधीकरण के अभिशाप से मुक्त कराना है। इसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश भी करेंगे कि वह सालभर में इस काम को पूरा करे। ज्यादातर विपक्षी सांसदों ने नई सरकार से सवाल किया कि जो सपने दिखाए जा रहे हैं उसे वे पूरा कैसे करेंगे।

दो दिन चली बहस के दौरान प्रधानमंत्री ने करीब-करीब सभी मुद्दों को छूने का प्रयास किया और विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा 'दुनिया में हमारी पहचान स्कैम इंडिया की बन चुकी है। लेकिन हमें अब स्किल्ड इंडिया की पहचान बनानी है।'

(दै.भा.एवं रा.प., 12.06.14)

ग्राम पंचायतों का होगा पुनर्गठन

राज्य में अगले साल पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं। मद्देनजर पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला परिषद ने सभी विकास अधिकारियों से तीन हजार की जनसंख्या वाले राजस्व गांवों की सूची मांगी है।

राज्य में वर्ष 1991 के बाद से ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन नहीं हुआ है। जबकि प्रदेश के गांवों में आबादी का काफी विस्तार हो गया है। ऐसे में ग्राम पंचायतों के फिर से पुनर्गठन की जरूरत महसूस की जाने लगी है। वर्ष 2011 के आधार पर तीन हजार की जनसंख्या वाले गांवों को यदि ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाता है तो कई नई पंचायतों का गठन हो सकता है।

(रा.प., 06.05.14)

भारत बना तीसरी आर्थिक शक्ति

विश्व बैंक समूह से जुड़े अंतरराष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (आईसीपी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत कड़े आर्थिक फैसलों के चलते आखिर तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। 2005 से 2011 के बीच सिर्फ छह साल में भारत ने जापान को पछाड़ते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना हुआ है, जबकि चीन दूसरे नंबर पर है।

हमारा देश 2005 से पहले 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। रिपोर्ट के मुताबिक परचेजिंग पावर पैरेटी यानि पीपीपी के आधार पर 2011 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 5.75 लाख करोड़ रुपए था, जबकि जापान का 4.38 लाख करोड़ रुपए था। वर्ष 2005 में भारत की जीडीपी 2.34 लाख करोड़ थी।

(रा.प.एवं दै.भा., 01.05.14)

अब जनता नहीं, पार्षद चुनेंगे महापौर

प्रदेश में महापौर और अन्य निकाय प्रमुखों का निर्वाचन अब निर्वाचित पार्षद करेंगे। राज्य सरकार ने सीधे जनता से महापौर चुनने की निर्वाचन प्रणाली खत्म करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस संबंध में स्वायत शासन विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।

विभाग के प्रमुख सचिव डी.बी.गुप्ता ने बताया कि महापौर के निर्वाचन नियमों में बदलाव कर आदेश जारी किया जाएगा। नवंबर में प्रदेश के निकायों के चुनाव में बहुमत प्राप्त पार्षद दल का नेता महापौर बनेगा। *(रा.प., 04.06.14)*

राज्य में बनेगा स्पेशल प्लानिंग बोर्ड

प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए योजना बनवाने और उन्हें मंजूरी देने के लिए स्पेशल प्लानिंग बोर्ड बनेगा।

प्रस्तावित राजस्थान स्पेशल प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट प्लानिंग बिल 2014 में यह प्रावधान किया गया है। नगरीय विकास विभाग ने इस बिल का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे जांच के लिए विधि विभाग को भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मंशा के अनुरूप बनाए गए इस बिल के प्रावधानों के तहत गांव, क्षेत्र विशेष या एक पूरे जोन की भविष्य की आवश्यकता के अनुसार नियोजित विकास किया जा सकेगा। *(रा.प.एवं दै.न., 28.06.14)*

नये विधायकों के हाथ लगी लॉटरी

प्रदेश के आधे से ज्यादा विधायकों के हाथ इस बार विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमएलए लेड) में लॉटरी लग गई है। राज्य में 200 में से 117 विधायक ऐसे हैं, जिन्हें अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए एक करोड़ से लेकर छह करोड़ रुपए तक की बकाया राशि मिली है।

एमएलए लेड के तहत मार्च 2013 तक प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 271 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए थे। मार्च 2014 को 399 करोड़ रुपए और जारी कर दिए गए। अधिकतर विधायक चुनाव से पहले स्वीकृत राशि खर्च करना चाहते थे, ताकि विकास के नाम पर वोट मिल सकें, लेकिन समय पर स्वीकृति नहीं मिलने से ज्यादातर पैसा पड़ा रह गया। इस बकाया राशि 670 करोड़ रुपए, अब चुनकर आये विधायक अपने क्षेत्र के विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। *(दै.भा., 29.05.14)*

प्रदेश को मिली 20 नई परियोजनाएं

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन की ओर से फेज-2 के लिए फरवरी में की गई 750 मेगावाट परियोजनाओं की नीलामी जीतने वाली कंपनियों में से 50 फीसदी से ज्यादा राजस्थान में निवेश करेंगी। राजस्थान रिन्युएवल एनर्जी कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक तथा आईएएस अधिकारी बी. के. देसी का कहना है कि इस नीलामी में से 370 मेगावॉट परियोजनाओं के लिए करीब 20 नई कंपनियां राजस्थान में निवेश करने जा रही हैं। इसमें अनुमानित निवेश करीब 3000 से 3500 करोड़ रुपए का होगा।

प्रदेश में परियोजना लगाने के लिए भू-आवंटन के बाद इन कंपनियों को एक साल के भीतर परियोजना को पूरा करना होगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के फेज-1 में 500 मेगावॉट के लिए राजस्थान में निवेश किया गया था। राजस्थान में फिलहाल 689 मेगावॉट की 124 सौर ऊर्जा परियोजनाएं संचालित हैं। *(दै.भा., 01-.04.-14)*

बिजली देगी झटका !

आमजन पर बिजली का भार बढ़ाने की तैयारियां फिर शुरू हो गई है। प्रदेश की तीनों कंपनियों ने अपनी कंगाली का हवाला देते हुए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में बिजली दरों की समीक्षा के लिए याचिका दायर की है।

हालांकि, कंपनियों व आयोग की तरफ से यह खुलासा नहीं किया गया है कि बिजली दामों में कितनी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। लेकिन सूत्रों के अनुसार सभी श्रेणियों में बिजली के दाम 18 से 19 फीसदी तक बढ़ाने की सिफारिश की बात सामने आई है। *(रा.प., 07.06.14)*

लगेगा फ्यूल सरचार्ज का करंट

प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से फ्यूल सरचार्ज का करंट लगेगा। राजस्थान डिस्कॉम ने विछले वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में कोयला, डीजल व परिवहन के अतिरिक्त खर्च के चलते बिजली की बढ़ी लागत का आकलन किया है, जिसके हिसाब से उपभोक्ताओं से चार पैसै प्रति यूनिट की वसूली निकाली गई है। कंपनियां यह राशि उपभोक्ताओं से अगले बिल में एकमुश्त वसूलेगी।

दरअसल, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग हर साल डिस्कॉम की बिजली खरीद समेत अन्य खर्च की गणना के बाद उपभोक्ताओं से वसूलने वाली विद्युत दर तय करता है। इस कवायद में आयोग फिक्स कॉस्ट के साथ ही वेरिएबल कॉस्ट के रूप में बिजली की दर निर्धारित करता है। वेरिएबल कॉस्ट कोयला डीजल व परिवहन खर्चे के अनुसार ऊपर-नीचे होती रहती है, जिसकी वसूली उपभोक्ताओं से करने के आयोग के निर्देश हैं। *(रा.प., 26.05.14)*

बढ़ गई बिजली चोरी की वारदातें

प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां पहले से ही करोड़ों का घाटा दिखा रही है। विधानसभा चुनाव के पहले जनप्रतिनिधियों द्वारा सवाल खड़ा करने पर तत्कालीन सरकार ने बिजली चोरों पर दरियादिली दिखाई थी।

नतीजतन, प्रदेशभर में विजिलेंस चैकिंग के अभियंताओं ने मासिक जांच के लक्ष्य आधे कर दिए थे। इससे बिजली चोरों का मनोबल बढ़ गया और उन्होंने चुनावों के दौरान जमकर बिजली चोरी की। इससे चुनावी साल में बिजली वितरण कंपनियों को करीब 1100 करोड़ रुपए का फटका लगा है।

अब बिजली चोरों को दी गई छूट का सीधा भार जनता पर आएगा, क्योंकि छीजत में बढ़ोतरी पर कंपनियों का घाटा बढ़ेगा। इस घाटे को कंपनियां प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग में पेश कर बिजली की दर में बढ़ोतरी के लिए याचिका दायर करती है। स्वीकृति पर इसका भार आम उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है। *(रा.प., 07.04.14, 19.06.14)*

सुधरेगा प्रदेश का बिजली सिस्टम

राज्य में बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अब राज्य व केन्द्र सरकार मिलकर काम करेंगी। बिजली वितरण एवं प्रसारण की तमाम जरूरतों का आकलन करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार के आला अधिकारियों की एक समिति का गठन कर दिया गया है। यह समिति तीन सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट देगी।

केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राज्य के ऊर्जा मंत्री गजेन्द्र खींवसर और राज्य व केन्द्र सरकार के तमाम आला अधिकारियों ने इसके लिए मैराथन बैठक कर राज्य में बिजली वितरण व प्रसारण की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन जारी रखने पर बल दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रदेश में 24 घंटे घरेलू बिजली आपूर्ति के मिशन को 18 महीने में पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। *(दै.भा.एवं दै.न., 18.06.14)*

मोदी सरकार लगाएगी सोलर प्लांट

क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार देश में चार बड़े सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रही है। यह प्लांट राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगाए जाएंगे। इनमें प्रत्येक की क्षमता 1000 मेगावॉट होगी। इसके साथ ही मंत्रालय क्लीन एनर्जी और परंपरागत बिजली को एक साथ मिलाने की योजना पर भी काम कर रहा है, ताकि क्लीन एनर्जी पैदा करने की कॉस्ट को कम किया जा सके।

अभी देश में सूरज की रोशनी से 2650 मेगावॉट बिजली बनाने की क्षमता स्थापित की गई है। देश के किन इलाकों से अधिक से अधिक सोलर ऐनर्जी हासिल की जा सकती है इसके लिए सरकार सर्वे भी कर रही है। सरकार का इरादा 2022 तक 20 हजार मेगावॉट सोलर एनर्जी पैदा करने का है। *(रा.प., 07.06.14)*

रिन्यूअल एनर्जी की है अपार संभावना

रिन्यूअल एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान ने देशभर में अपनी अलग पहचान बना ली है। फिर चाहे विण्ड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी, हर क्षेत्र के लिए मरुधरा में अपार संभावना है। बस जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार रिन्यूअल एनर्जी क्षेत्र के निवेशकों की फील्ड में आ रही दिक्कतों को समझे और उनके निवारण के लिए कदम उठाए। अगर ऐसा हुआ तो रिन्यूअल एनर्जी के क्षेत्र में पांच साल में राजस्थान का नाम मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आएगा।

जयपुर में एसोचैम और रिन्यूअल एनर्जी मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सोलर-विण्ड पावर कॉन्फ्रेंस में यह उभर कर सामने आया। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के सचिव जी.के.शर्मा ने बताया कि सरकार रिन्यूअल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और निवेशकों की सहुलियत के लिए रेग्यूलेशन बनाए हैं। *(रा.प., 02.05.14)*

मरुधरा की 'कोख' पर गहराता संकट

प्रदेश में पानी की बर्बादी ने मरुधरा की कोख में छिपे जलभंडारों को जोखिम में ला दिया है। करीब पांच साल पहले बड़े जोर-शोर से वर्षा जल संग्रहण के दावों के बावजूद प्रदेश में निर्धारित स्थानों में से 25 फीसदी पर भी वर्षा जल संग्रहण ढ़ांचों का निर्माण नहीं हो पाया। यही कारण है कि पिछले तीन सालों की जोरदार बारिश के बावजूद भी भूजल के हालात भयावह होते जा रहे हैं। प्रदेश का करीब 85 फीसदी हिस्से का भूजल तेजी से सूखता जा रहा है।

प्रदेश के 243 में से 172 ब्लॉक्स भूजल की दृष्टि से अतिदोहित की श्रेणी में आ चुके हैं। इसके अलावा करीब 30 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनका भूजल तो समाप्त होने के कगार पर जा पहुंचा है। इसके अलावा करीब 15 ब्लॉक्स और हैं जो आने वाले दिनों में इस सूची में शामिल हो सकते हैं। कहने को तो डार्कजोन में आने वाले क्षेत्रों में ट्यूबवेल खुदाई पर रोक है लेकिन मिलीभगत के चलते धड़ल्ले से ट्यूबवेल खोदे जा रहे हैं।

(रा.प., 04.05.14 एवं रा.स., 01.06.14)

जनता को मिले पीने का साफ पानी

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सख्त हिदायत दी है कि दूषित पेयजल सप्लाई को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की बरती गई कोताही के लिए जिम्मेदार अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता।

उन्होंने यह निर्देश मौसम जनित बीमारियों से निपटने और स्वच्छ जल सप्लाई को लेकर आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिया। राजे ने कहा कि पेयजल सप्लाई लाइनों में लीकेज चिह्नित कर उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। सप्लाई किए जाने वाले जल का मेडिकल कॉलेज भी नियमित रूप से नमूने लें। दूषित पानी पाए जाने पर कार्रवाई की जाए। *(रा.प., 14.05.14)*

पानी को तरस रहे हैं 800 गांव

झालावाड़ जिले में भले ही सरकार ने पिछले दस सालों के दौरान पेयजल योजनाओं के लिए करीब एक हजार करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हों, लेकिन अब भी जिले के करीब 50 फीसदी गांवों के लोग पेयजल के लिए हैण्डपंपों व कुओं के भरोसे ही हैं। गर्मी के दिनों में हैण्डपंप व कुओं का जल स्तर गिरने से ग्रामीणों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ता है।

वैसे तो यह जिला नदियों व तालाबों के मामले में समृद्ध है, इसके बावजूद हर साल गर्मी में पेयजल की समस्या खड़ी हो जाती है। इसके लिए जलदाय विभाग की नीतियां जिम्मेदार है। अभी भी जिले के 1625 गांवों में से करीब 800 गांवों में नलों से पानी नहीं पहुंच पाया है।

(रा.प., 08.04.14)

नहीं समझ रहे पानी का मोल

प्रदेश के शहरों में जितना पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है, उसका करीब आधा अन्य कामों में खर्च हो रहा है। जलदाय विभाग के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में रोजाना 28 हजार 450 लाख लीटर पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसमें से करीब 14 हजार 225 लाख लीटर ही पीने, नहाने, रसोई व कपड़े धोने में काम आता है। बाकी का पानी शौचालय, बागवानी, फर्श व वाहन धोने आदि में खर्च किया जा रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति को पीने, नहाने, रसोई व कपड़े धोने के लिए रोजाना अधिकतम 40 लीटर पानी की जरूरत होती है। वर्तमान में प्रदेश के एक लाख तक की आबादी के शहरों में 70 से 100 लीटर पेयजल प्रति व्यक्ति सप्लाई किया जा रहा है। यदि प्रदेश में सभी के लिए पेयजल की उपलब्धता के लिहाज से गंदे पानी का द्वितीय परिशोधन कर पेयजल के अलावा अन्य काम के उपयोग के लिए सप्लाई किया जाए तो साढ़े तीन करोड़ से भी ज्यादा लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। *(रा.प., 06.04.14)*

बदलना होगा पुराना ढर्रा : वसुंधरा

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि पेयजल की समस्या से निपटने के लिए पुराने ढर्रे को बदलने की जरूरत है। हमें नई सोच और तकनीक के साथ इस दिशा में काम करना होगा। भूजल की बजाय सतही जल पर आधारित प्रोजेक्ट और नदियों को जोड़ने जैसे काम करने होंगे।

मुख्यमंत्री ने जयपुर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इंजीनियर्स की कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य में अब तक बिना किसी दूरदृष्टि के पुराने ढर्रे से ही काम किया जा रहा है, लेकिन अब सोच बदलनी होगी। हमें गर्मी के दिनों में कन्टीजेंसी प्लान बनाने और टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई जैसे तौर-तरीकों से बाहर निकलना होगा। नदियों को जोड़ने, पानी को संचित कर भूजल बढ़ाने जैसे कार्यक्रमों पर जोर देना होगा।

(दै.न. एवं रा.प., 14.06.14)

गांवों में पानी के लिए 2300 करोड़

नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम के तहत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का साफ पानी पहुंचाने के मकसद से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 2300 करोड़ रुपए की वार्षिक पेयजल योजना स्वीकृत की है।

योजना के दायरे में राज्य के 3173 गांव और ढाणियां आएंगे। इन गांवों और ढाणियों की पेयजल गुणवत्ता बेहद खराब है। शुरुआती प्रस्तावों के आधार पर जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, बीकानेर के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत कर इसके लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इन जिलों के 833 गांवों और ढाणियों में पेयजल गुणवत्ता सुधारने, पेयजल सप्लाई बढ़ाने, पाइपलाइन बिछाने से लेकर ट्यूबवेल लगाने का काम किया जाएगा।

योजना के तहत जोधपुर, बाड़मेर, भरतपुर, जालौर, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, झुंझनूं, चूरू और नागौर में 668 रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) प्लांट लगाए जाएंगे। इस पर करीब 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। *(दै.भा., 24.06.14)*

नदियों को जोड़ कर भरेंगे भूजल

राज्य सरकार ने नदियों को जोड़ने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सरकार ने माही बेसिन की बुनन्दी व चम्बल बेसिन की आहू नदी पर दो पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस योजना से किसानों को भी जोड़ा जाएगा। यह प्रोजेक्ट सफल हुआ तो राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा, जिसने नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया है।

'फॉर वाटर्स कॉन्सेप्ट' के तहत जल संग्रहण विकास के लिए आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह जानकारी देते हुए कहा कि हम इस काम को पांच साल में पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में किसानों व आमजन की उचित भागीदारी होगी और पानी का मालिकाना हक भी उन्हीं के पास रहेगा। भूजल स्तर बढ़ाने और जल प्रबंधन के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

(रा.प.एवं दै.भा., 30.05.14)

पकड़वाएं बाल श्रम के गुनहगारों को

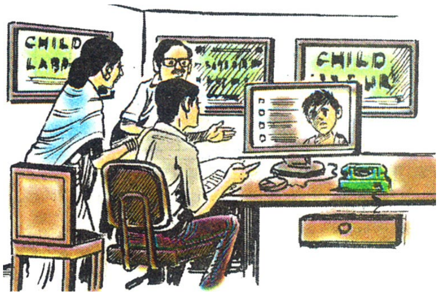

यदि आपके घर या ऑफिस के आस-पास कोई बच्चों से मजदूरी करा रहा है तो आप उसकी शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर सभी जानकारी और मार्ग-दर्शन उपलब्ध होगा। आपकी शिकायत पर प्रशासन सम्पर्क कर बाल श्रमिकों को मुक्त कराने और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

छोटी उम्र के बच्चों से बाल श्रम कराने वाले गुनहगारों को आप अब घर बैठे पकड़वा सकेंगे। गुनहगारों पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन जल्द ही वेबसाइट शुरू कर आम आदमी के माध्यम से बाल श्रमिकों से काम कराने वालों की शिकायत ऑनलाइन प्राप्त करेगा। शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

इस काम में प्रशासन को मदद करने वाले जन सहयोगी को जिला स्तर और राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। इस वेबसाइट का प्रभारी आईएएस अधिकारी को बनाया जाएगा और इसका कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट परिसर में होगा। *(दै.न., 13.06.14)*

सड़क किनारे प्रसव सरकार दे हर्जाना

तीन साल पहले भीलवाड़ा में सरकारी डॉक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही से सड़क किनारे प्रसव होने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव से पीड़ित महिला को 50 हजार रुपए हर्जाना देने को कहा है।

महिला तीन अगस्त 2011 को भीलवाड़ा के करेड़ा राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र में पुरुष चिकित्सक के पास गई, तो उसे स्वास्थ्य केन्द्र भेज दिया गया था। स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे स्वास्थ्य केन्द्र की महिला चिकित्सक के पास ले जाया गया। लेकिन इसी दौरान महिला ने सड़क किनारे बच्चे को जन्म दे दिया। मामले की जांच में आयोग ने स्वास्थ्य केन्द्र के पुरुष नर्सिंग स्टाफ को दोषी माना और सरकार पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। यह राशि पीड़ित महिला को दी जाएगी। *(रा.प, 17.04.14)*

मातृ मृत्यु दर में आई कमी

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1990 से 2013 के बीच मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन पिछले वर्ष वैश्विक मातृ मृत्यु की एक तिहाई मौतें नाइजीरिया और भारत में हुई। वर्ष 1990 से 2013 के बीच मातृ मृत्यु आकलन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 1990 से गर्भधारण संबंधी जटिलताओं के कारण और प्रसव के दौरान 5,23,000 महिलाओं की मौत हुई वहीं 2013 में 2,89,000 महिलाओं की जान गई। मातृ मृत्यु दर में 45 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इनमें से 62 प्रतिशत मौतें उप सहारा अफ्रीका और 24 प्रतिशत महिलाओं की मौत दक्षिणी एशिया में हुई। भारत में मातृ मृत्यु दर में 1990 की तुलना में 2013 में 65 प्रतिशत की गिरावट आई है। *(रा.प., 08.05.14)*

सुधरेगी मिड-डे मील की गुणवत्ता

सरकारी विद्यालयों में मिड-डे मील योजना का क्रियान्वयन प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो, इसके लिए राज्य स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सभी विद्यालयों के विकास के लिए अधिकारियों से सर्वे कराया जाएगा और राजकीय विद्यालयों की वास्तविक स्थिति पता लगाने की कवायद की जाएगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और रिपोर्ट देने की बात कही गई है।

मिड-डे मील में खाद्यान्न की हर स्तर पर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी, यहां तक की बचे हुए भोज्य पदार्थ को भी सही तरीके से रखने के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सभी विद्यालयों में किचन शेड बनाए जाएंगे तथा भोजन पकाने के लिए गैस कनेक्शन की व्यवस्था की जाएगी। *(दै.न., 17.06.14)*

बाल विवाह है गैर-जमानती अपराध

बाल विवाह की रोकथाम के उद्देश्य से शादी के कार्डों पर वर-वधु की उम्र लिखना अनिवार्य करने के सरकार के आदेश के बावजूद प्रदेश में कानून को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। जिला प्रशासन ने किसी भी प्रिन्टिंग प्रेस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 साल से कम उम्र की बालिका और 21 वर्ष से कम उम्र के युवक का विवाह करना गैर-जमानती अपराध है।

बाल विवाह में सम्मिलित होने पर एक लाख रुपए तक जुर्माना और दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके बावजूद गांवों में ही नहीं बल्कि शहरों तक में बाल विवाह धड़ल्ले से होते देखे जा रहे हैं। हालांकि बाल विवाह पर रोक के लिए प्रत्येक उपखंड मजिस्ट्रेट को बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने भी सभी उपखंड अधिकारियों को बाल विवाह रोकथाम के आदेश दे रखे हैं। *(दै.भा., 22.04.14)*

बेटियां भी बेटों से कमतर नहीं-स्मृति

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि बेटियां भी बेटों से किसी मायने में कमतर नहीं है। यह बात उन्होंने भोपाल के एक मॉडल स्कूल में छात्र-छात्राओं से वार्तालाप के दौरान ग्यारहवीं कक्षा की एक छात्रा द्वारा भ्रूण हत्या पर किए गए सवाल के जवाब में कही।

उन्होंने कहा कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मां को यह संकेत दिया गया था कि बेटी बोझ है, इसे मार दो, तो ही तुम्हारा जीवन सफल है और सुखी भी। मैं आज सार्वजनिक तौर पर अपनी मां को धन्यवाद देती हूं कि उनमें इतनी क्षमता थी, शक्ति थी कि भले ही जेब में पैसा न हो, उन्होंने अपनी बेटी की हत्या नहीं की।

उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या अमानवीय कृत्य है, पाप है और कानूनी रूप से अपराध है। आज किस कदर बेटियां शिक्षा और अपने स्वयं के बल-बूते पर सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा बिखेर रही हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। *(दै.भा., 28.06.14)*

महिला बैंक खोलेगा शाखाएं

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश में महिला बैंक की शुरुआत की है। बैंक की अध्यक्ष उषा अनन्त सुब्रह्मण्यम ने कहा कि पिछले सात माह की अवधि में भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) का शाखा नेटवर्क बढ़कर 23 के स्तर पर हो गया है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष में 55-60 नई शाखाएं और खोलेगा। बैंक ग्रामीण क्षेत्र में भी 20 प्रतिशत शाखाएं खोलने की आवश्यकता को भी पूरा करेगा। उन्होंने कहा बैंक महिलाओं का सशक्तिकरण बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से करना चाहता है।

बैंक महिलाओं को वित्तीय सहयोग देकर महिला उद्यमता को बढ़ावा देने और खासतौर पर समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने पर जोर देगा। पिछले साल सभी राज्यों की राजधानियों में महिला बैंक की शाखाएं खोली जा चुकी हैं। *(न.ज़ु., 18.04.14)*

सड़क सुरक्षा

ट्रैफिक नियमों की समझ बढ़े तो बचे जिंदगी

सड़कों पर दौड़ते वाहनों की रेलम-पेल के बीच वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें, ड्राइविंग सेंस को समझते हुए वाहन चलाएं तो अपनी और दूसरों की जिन्दगी बचा सकता है। इसमें एक यातायात पुलिसकर्मी की भूमिका भी अहम होती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पुलिस एकादमी (आरपीए) में सड़क हादसों को रोकने और यातायात प्रबंधन की जानकारी देने के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

सड़क हादसों में हर साल 1200 मौत

- *जयपुर जिले में हर साल चार हजार से अधिक दुर्घटनाओं में 1200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं।*
- *परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में हर रोज औसतन 65 दुर्घटनाओं में 26 लोगों की मौत और 75 से अधिक लोग घायल होते हैं। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं गलत ड्राइविंग या ओवरलोडिंग के कारण होती है।*
- *वर्ष 2012 में हुई 22969 दुर्घटनाओं में से 21939 का कारण चालकों की लापरवाही रही, जो कि कुल दुर्घटनाओं का 95 प्रतिशत है।*
- *राजस्थान में सर्वाधिक मौतें नेशनल हाईवे-8 पर हो रही है। वर्ष 2012 में यहां 922 एवं नेशनल हाईवे-11, जो आगरा से बीकानेर को जोड़ता है, उस पर 556 लोगों की मौतें हुई।*

कार्यशाला में आरपीए के निदेशक बीएल सोनी (एडीजी) ने सड़क पर मानव की सुरक्षा के लिए ड्राइविंग हैबिट्स और प्रोटेक्टिव पुलिसिंग पर बल देते हुए कहा कि यदि ऐसा हो तो सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

कार्यशाला के पहले सत्र में राजसमंद के जिला परिवहन अधिकारी वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि अक्सर वाहन चालक ड्राइविंग के समय लेन सिस्टम, रोड सिग्नल्स, रोड साइन और ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते। इससे दुर्घटनाएं होती है। उन्होंने प्रदेश में ट्रैफिक यूनिवर्सिटी और यातायात शोध संस्थान बनाए जाने की जरूरत बताई।

दूसरे सत्र में पीपुल्स ट्रस्ट की हैड और सेंटर फॉर रोड सेफ्टी की कॉर्डिनेटर प्रेरणा सिंह ने सुरक्षित ड्राइविंग की आधारभूत जानकारियों पर व्याख्यान देते हुए बताया कि ड्राइविंग करते समय स्पीड पर नियंत्रण बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। तेज स्पीड होने पर अचानक किसी के सामने आने पर वाहन रोकना बहुत मुश्किल होता है। तीसरे सत्र में सेवानिवृत्त अधिकारी डीपी सैनी ने रोड एक्सीडेंट से संबंधित कानूनी प्रावधान, मोटर वाहन एक्ट और आरपीसी एक्ट के बारे में जानकारी दी। कार्यालय में हैड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर तक के 71 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। *(दै.भा., 05.05.14, 06.05.14)*

पर्यावरण

ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में भारत सबसे गंभीर देश

ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के प्रति संवेदनशीलता और प्रयासों के मामले में भारत सबसे आगे निकल रहा है। दूसरी तरफ इस मोर्चे पर सबसे ज्यादा हो-हल्ला मचाने वाले अमरीका के प्रयास अभी भी सवालों के घेरे में हैं।

यह बात टाइम पत्रिका द्वारा कराए गए एक वैश्विक सर्वे में सामने आई है। छह देशों पर किए गए सर्वे में भारतीयों ने ऊर्जा और उसकी खपत को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। भारतवासी ऊर्जा संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन घटाने की अपनी क्षमता को लेकर सबसे ज्यादा आशावादी थे। ऑनलाइन कराए गए इस सर्वे में अमरीका, ब्राजील, जर्मनी, तुर्की, भारत और कोरिया से कुल 3,505 लोगों को समान संख्या में शामिल किया गया।

सर्वे में 10 में से नौ भारतीयों ने कहा कि उनके लिए संरक्षण के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। सर्वे में शामिल सभी देश अलग-अलग तरीकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं। जर्मनी के लोग अपने कम्प्यूटर बन्द करने में, ब्राजील के लोग लाइट बन्द करने और अमरीका के लोग रीसाइक्लिंग में आगे हैं। लेकिन भारतीयों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति सर्वाधिक व्यापक दृष्टिकोण दिखा। 10 में से 8 भारतीयों ने कहा कि ऊर्जा खपत पर अंकुश लगाने के लिए वे व्यक्तिगत आदतों में भी सचेत हैं। भारतीय लोग सार्वजनिक वाहन पर चलने की अपेक्षा पैदल चलने के मामले में सबसे ज्यादा आशावादी हैं। भारतीय जलवायु मुद्दों की व्यापक जानकारी रखते हैं। लगभग 60 फीसदी भारतीयों का मानना है कि वर्ष 2050 तक दुनिया कार्बन उत्सर्जन में 80 फीसदी तक कमी ला सकती है। *(रा.प., 19.06.14)*

दूरसंचार सेवाएं

कॉल ड्राप से कमाई

मोबाइल पर बात करते समय बीच में ही कॉल कटने (कॉल ड्राप) का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ऐसा एक या दो बार ही नहीं, बल्कि बार-बार हो रहा है। जिससे उपभोक्ताओं को चंद मिनट की बात के लिए कई कॉल करने पड़ रहे हैं। यानि जो बात एक कॉल के जरिए हो सकती है उसके लिए तीन-चार कॉल करने पड़ते हैं।

कॉल ड्राप के जरिए उपभोक्ताओं की जेब पर भार डालने का ऐसा ही खेल चल रहा है। मोबाइल ऑपरेटर यह खेल हाईकोर्ट के उस आदेश की आड़ में कर रहे हैं जिसमें स्कूल और अस्पतालों आदि से टॉवर हटाने के लिए कहा गया है।

दूरसंचार क्षेत्र में कई मोबाइल ऑपरेटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अकेले राजस्थान में ही मुख्य रूप से आठ ऑपरेटर काम कर रहे हैं। जिनमें से तीन से चार आपरेटरों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को जोड़ने की स्पर्धा में कॉल दरों में इजाफा करना तो दूर बल्कि कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं।

इससे आपरेटर अपेक्षित कमाई का ग्राफ नहीं छू पा रहे। यही कारण है कि उपभोक्ताओं को दरकिनार कर कॉल ड्राप के जरिए कमाई कर रहे हैं। हालांकि ट्राई के द्वारा राजस्थान में एक सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें कॉल ड्राप के बारे में भी उपभोक्ताओं से प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन सर्वे रिपोर्ट पहले दिल्ली मुख्यालय जाएगी और वहीं से कार्यवाही तय होगी। इस प्रक्रिया में लम्बा समय लगेगा। *(रा.प., 09.04.14)*

वित्तीय सेवाएं

प्रीपेमेंट पर अब जुर्माना नहीं

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन आम बैंक ग्राहकों के हितों की रक्षा करने वाले फैसले ले रहे हैं। रिजर्व बैंक ने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लेने वाले ग्राहकों को भारी राहत देते हुए उन्हें समय से पहले बगैर किसी पेनाल्टी के कर्ज चुकाने की सुविधा दे दी है।

केन्द्रीय बैंक ने दिशा-निर्देश जारी कर बैंकों को इस बारे में सख्त निर्देश दिए हैं। इससे पहले रिजर्व बैंक ने न्यूनतम सीमा से कम जमा राशि रखने पर भी पेनाल्टी लगाने की व्यवस्था को खत्म कर दिया था। *(रा.प., 08.05.14)*

उपभोक्ता फैसले

ऑपरेशन से गई रोशनी, अस्पताल पर चार लाख का हर्जाना

उदयपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गांव कोकापुर निवासी सुभाष सेवक ने सागवाड़ा के पदमावती आई हॉस्पिटल के खिलाफ डूंगरपुर के उपभोक्ता मंच में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया गया कि उन्होंने उक्त हॉस्पिटल के डॉ. दिलीप शाह से मोतियाबिंद निकलवाने के लिए आंख का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद उस आंख की रोशनी समाप्त हो गई।

उन्होंने मुंबई के कांदीवली स्थित आई हॉस्पिटल व दाहोद के अस्पताल में आंख की सर्जरी भी कराई मगर उस आंख की रोशनी नहीं लौटी। डूंगरपुर के उपभोक्ता मंच ने उनके परिवाद को खारिज कर दिया।

सुभाष सेवक ने इसकी अपील राज्य उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराई। आयोग ने मामले की सुनवाई व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पदमावती आई हॉस्पिटल को ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का दोषी माना। आयोग ने हॉस्पिटल को आदेश दिया कि वह सुभाष सेवक को चार लाख ग्यारह हजार रुपए का हर्जाना अदा करें। *(दै.भा., 24.04.14)*

दावा तो किया था, फिर भी नहीं चमके दांत !

जोधपुर निवासी 72 वर्षीय रामकृष्ण ने एक नामी टूथपेस्ट कम्पनी के खिलाफ उपभोक्ता मंच में परिवाद दायर किया। उन्होंने अपने परिवाद में बताया कि चौदह दिन तक दो बार ब्रश करने के बावजूद उनके दांत पीले ही रहे। जबकि कम्पनी का दावा था कि टूथपेस्ट से ब्रश करने पर उनके दांत सफेद हो जाएंगे और चमकने लगेंगे। उन्होंने कम्पनी के विज्ञापन को आम उपभोक्ता को भ्रमित करने वाला बताया।

मामले की सुनवाई पर कम्पनी की ओर से कहा गया कि यह चाइना में हुए रिसर्च वर्क का परिणाम था। कम्पनी की ओर से यह भी दलील दी गई कि दवा व चाय से जो दांत पीले हो जाते हैं वह कई बार सफेद नहीं होते हैं। लेकिन मंच ने कम्पनी के विज्ञापन को भ्रामक माना और उपभोक्ता को पांच हजार रुपए की क्षतिपूर्ति सहित टूथपेस्ट की कीमत लौटाने का आदेश दिया। जिला मंच ने कम्पनी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना जमा कराने के आदेश भी दिए गए थे।

इस आदेश के खिलाफ कम्पनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दर्ज कराई। लेकिन आयोग ने जिला मंच के फैसले को बरकरार रखा। इसके अलावा आयोग ने कम्पनी को दस हजार रुपए अलग से उपभोक्ता रामकृष्ण व्यास को अदा करने के आदेश भी दिए हैं। *(रा.प., 19.05.14)*

खास समाचार

मिलावटखोरों को नहीं बख्शेगी सरकार

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मिलावटखोरों को माफ नहीं करके यह संदेश दिया है कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। राजे ने दूध में मिलावट कर कम गुणवत्ता युक्त दूध बेचने के एक प्रकरण में आरोपी को सजा माफी से इंकार कर दिया है।

उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों की सजा कम करने से उनके हौसले बुलंद होंगे और वे फिर मिलावट कर लोगों की जिन्दगी को खतरे में डालने से बाज नहीं आएंगे। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

मामले के अनुसार श्रीगंगानगर जिले के सुरेन्द्र कुमार को न्यायालय ने 6 माह के कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में उच्च न्यायालय ने कारावास की सजा को आर्थिक दण्ड में बदलने का सरकार से अनुरोध किया था। लेकिन मामला लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा होने के कारण मुख्यमंत्री ने इस सजा को बरकरार रखा। *(दै.न., 06.06.14)*

खाद्य सामग्री की होगी दोहरी जांच

बाजार में बिकने वाले मिलावटी व असंरक्षित खाद्य पदार्थों की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अब तीन के बजाय चार सैंपल लेने पड़ेंगे, जिनमें से एक स्टेट या पब्लिक फूड लैब तथा दूसरा राष्ट्रीय स्तर की नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर लैबोरेट्री (एनएबीएल) को भेजना होगा। इससे जांच की विश्वसनीयता बनेगी और रिपोर्ट में गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी।

इस बारे में केन्द्र सरकार की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) नई दिल्ली की निदेशक (क्वालिटी एश्योरेंस) डॉ. संध्या काबरा ने सभी राज्यों के फूड सेफ्टी कमिश्नरों को सर्कुलर भेजा है। दोनों की जांच रिपोर्ट आने पर खाद्य विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।

जांच में फूड सैंपल असुरक्षित पाए जाने पर 10 लाख रुपए जुर्माना से लेकर उम्रकैद की सजा, घटिया सामग्री पाए जाने पर 5 लाख रुपए तथा मिसब्रांड मिलने पर 3 लाख रुपए का जुर्माना व सजा का प्रावधान है। *(दै.भा., 30.05.14)*

उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

जागो ग्राहक जागो

'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (कट्स कार्ट) द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण करने, शिकायतों से संबंधित सूचना एवं सलाह सेवाएं देने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है। कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत या समस्याओं के बारे में स्वयं व्यक्तिश कार्यालय समय में डी-218, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है अथवा नीचे लिखे फोन, फैक्स व ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रेषित कर सकता है।

30 1983 2012 CUTS International

फोन: 141-2282823, 2282482, 5133259, फैक्स: 141-4015395
ईमेल: cart@cuts.org, वेबसाइट: www.cuts-international.org

कट्स कार्ट

स्त्रोत: रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, बी.एल.: बिजनेस लाइन

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोन: 91.141.513 3259 फैक्स: 228 2485, टेलीफैक्स: 401 5395, ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।